राजन गुप्ता और मंजरी नेहरू कौल से पहले, जे. जे.के सम्मुख

पूनम-याचिकाकर्ता

बनाम

भूपेंद्र प्रतिवादीगणओं 2015 का एफ. ए. ओ. सं. 77

29 अक्टूबर, 2019

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, धारा 13 (1) (i-a)-तलाक-क्रूरता-पक्षकारों की 17 वर्षीय बेटी का यह कथन कि वह अपनी मां के बजाय छात्रावास में रहना पसंद करती है, स्थिति को समझने के लिए परिपक्व है और उसे प्रताड़ित नहीं माना जा सकता है-इसके अलावा, पति के खिलाफ कई आपराधिक शिकायतें दर्ज करने में पत्नी के कार्य और आचरण, जिला परिषद चुनाव में उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की उसकी अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार तथ्य पक्षों के बीच गंभीर वैवाहिक कलह के लक्षण हैं-इस प्रकार, न केवल बच्चों के प्रति, बल्कि पति के प्रति भी पत्नी के आचरण से बहुत मानसिक पीड़ा हुई-इसलिए, तलाक के आदेश को बरकरार रखा गया।

यह मानते हुए कि, पीडब्लू-7/पूजा के बयान का उल्लेख करना सबसे अधिक प्रासंगिक होगा, जो पक्षों की बेटी है और एल. डी. के समक्ष अपने बयान के समय उसकी आयु लगभग 17 वर्ष थी। पारिवारिक न्यायालय।मान लीजिए, पार्टियों के बीच शादी 09.03.1996 पर हुई थी और पार्टियां 2009 तक एक साथ रहती थीं।इसका मतलब है कि अलग होने के समय यानी 2009 में पीडब्लू-7/पूजा की उम्र लगभग 13 साल थी।इस प्रकार, वह अपने माता-पिता के बीच मौजूद संबंधों की प्रकृति को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व थी।इसके अलावा, यह रिकॉर्ड पर स्वीकार किया जाता है कि वर्ष 2009 से, पीडब्लू-7/पूजा और उसका छोटा भाई दोनों प्रतिवादी-पिता के साथ रह रहे हैं।यह भी रिकॉर्ड की बात है कि दोनों बच्चों को पिता द्वारा बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था, हालांकि पति द्वारा उन्हें बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करने का कारण घर में व्याप्त अस्वस्थ और गैर-अनुकूल वातावरण था, जबकि दूसरी ओर, अपीलकर्ता-पत्नी ने आरोप लगाया कि यह प्रतिवादी-पति की अपने कर्मचारी के साथ कथित संलिप्तता के कारण था, बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पैक कर दिया गया था।इस पृष्ठभूमि में, पीडब्लू-7/पूजा का बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसने अपीलार्थी-माँ के घर के अंदर और बाहर दोनों के आचरण का स्पष्ट विवरण दिया है। उसकी गवाही को किसी भी तरह से एक प्रशिक्षित संस्करण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने भाई के साथ लगभग 13 वर्षों तक अपने माता-पिता के साथ रही थी और इसलिए, वे बड़े हो गए थे और इतने परिपक्व थे कि वे स्पष्ट रूप से पूनम बनाम भूपेंद्र को घर में व्याप्त पूरी स्थिति समझ सकते थे।

817 पूनम बनाम भूपेन्द्र

(मंजरी नेहरू कौल, जे.)

इतना ही नहीं, बेटी ने बयान दिया कि वह अपनी मां के साथ रहने के बजाय छात्रावास में रहना पसंद करती है, जो चंडीगढ़ में उसके स्कूल में जाती है और बदसूरत दृश्य पैदा करती है जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी होती है।कोई भी बेटी, बहुत कम, 17 साल की लड़की अपनी माँ के खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगाएगी। (पैरा 11)

आगे कहा कि निर्विवाद रूप से पक्ष पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से अलग रह रहे हैं।प्रत्यर्थी-पति के खिलाफ कई आपराधिक शिकायतें दर्ज करने में अपीलार्थी-पत्नी के कार्य और आचरण, इस तथ्य के साथ कि जिला परिषद के चुनावों में उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की उसकी अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच गंभीर वैवाहिक कलह के लक्षण हैं।

(पैरा 12)

आगे कहा कि हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि न केवल बच्चों के प्रति, बल्कि प्रतिवादी-पति के प्रति भी पत्नी के आचरण से बहुत मानसिक पीड़ा होती, जिससे पति को गहरा दुख होता और उनके वैवाहिक संबंध को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता।यह बहुत स्पष्ट है जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि 2009 से अलग रह रहे पक्षों के बीच किसी भी सुलह की कोई संभावना नहीं है।पार्टियों के साथ हमारी बातचीत ने हमें बिना किसी संदेह के छोड़ दिया है कि पार्टियों के बीच शादी टूट गई है।

(पैरा 13)

अपीलार्थी के लिए कोई नहीं

मनीष सोनी, अधिवक्ता(प्रत्यर्थियों के लिए)।

मंजरी नेहरू कौल, जे.

(1) एल. डी. द्वारा पारित 08 दिसंबर, 2014 के फैसले और डिक्री को चुनौती देते हुए पत्नी-पूनम द्वारा तत्काल अपील की गई है। जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गुड़गांव (इसके बाद 'एल. डी.' के रूप में संदर्भित। पारिवारिक न्यायालय '), जिसके माध्यम से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद' अधिनियम 'के रूप में संदर्भित) की धारा 13 के तहत प्रतिवादी-पति/भूपेंद्र द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी गई थी।

(2) तत्काल अपील के निर्णय के लिए आवश्यक कुछ तथ्य, जैसा कि प्रत्यर्थी-पति (उसमें याचिकाकर्ता) द्वारा एल. डी. के समक्ष दायर याचिका में अनुरोध किया गया था। पारिवारिक न्यायालय पर ध्यान दिया जा सकता है।

(3) दोनों पक्षों के बीच शादी 9 मार्च, 1996 को रेवाड़ी जिले के गाँव बोदिया कवालपुर में हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार संपन्न हुई थी।विवाह से एक बेटी और एक बेटे का जन्म क्रमशः 29 दिसंबर, 1996 और 14 दिसंबर, 1997 को हुआ था।पति के प्रति पत्नी का व्यवहार शादी की शुरुआत से ही अशोभनीय था।पत्नी ने पति पर अपने माता-पिता से अलग रहने का दबाव डाला।चूंकि पति ने मना कर दिया था, इसलिए पत्नी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया। गम्भीर प्रयासों और पति के बार-बार अनुरोध के बावजूद, पत्नी ने वैवाहिक जीवन में लौटने से इनकार कर दिया।अपनी शादी को बचाने के लिए, पति वर्ष 2001 में गाँव से सेक्टर 10-ए, गुड़गांव में एक अलग आवास में स्थानांतरित हो गया और 2003 तक वहाँ रहा। हालाँकि, इस व्यवस्था ने मामलों में बहुत कम मदद की क्योंकि समय बीतने के साथ पत्नी का व्यवहार बिगड़ता गया।पत्नी के अनुचित व्यवहार का बच्चों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और घर का माहौल खराब हो गया।आखिरकार, वर्ष 2009 में, पति अपने बच्चों के साथ गुड़गांव में ही एक अन्य फ्लैट में शिफ्ट हो गए, जबकि पत्नी उस फ्लैट में पीछे रह गई, जिसे पति ने एक दोस्त से किराए पर लिया था। पत्नी ने पति के खिलाफ धारा 323,452 और 506 आई. पी. सी. के तहत एक एफ. आई. आर. सहित झूठे और तुच्छ मामले दर्ज किए, जिसके परिणामस्वरूप पति को उस घर में प्रवेश करने से रोक दिया गया जहां वह रह रही थी।वह फिर भी उसके साथ तर्क करने और उसे प्रदान करने की कोशिश करता था।इसके बावजूद, उन्होंने धारा 125 Cr.P.C के तहत एक याचिका दायर की और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए, 406 के तहत एक झूठी शिकायत दर्ज की, लेकिन उसमें निहित आरोप झूठे पाए गए।इसके बाद उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और आईपीसी की धारा 498-ए, 406,506,323,307,494,468,471 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की, जो अभी भी लंबित थी।महिला प्रकोष्ठ, दिल्ली के समक्ष भी एक शिकायत की गई थी।जुलाई, 2010 में, जब पति ने जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ा, तो पत्नी ने जानबूझकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ा।उक्त चुनावों के प्रचार के दौरान, वह अपने परिवार के साथ उसे परेशान करने के एकमात्र इरादे से नकारात्मक प्रचार में शामिल हो गई। पत्नी द्वारा बनाए गए भद्दे दृश्यों के कारण, बच्चों ने भी उसके साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया और अपने स्कूल जाने से डर गए, क्योंकि वह वहां भी भद्दे दृश्य बनाती थी।नतीजतन, उन्हें बोर्डिंग स्कूलों में स्थानांतरित करना पड़ा ताकि उन्हें उन सभी अप्रियता से दूर रखा जा सके जो पत्नी पैदा करेगी। इसलिए, पति ने एल. डी. पारिवारिक न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। अधिनियम की धारा 13 के तहत उनकी शादी को भंग करने के लिए

(4) इसके विपरीत, अपीलार्थी-पत्नी (उसमें प्रत्यर्थी) ने अपने पति के आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन और खंडन किया।

819 पूनम बनाम भूपेन्द्र

(मंजरी नेहरू कौल, जे.)

एल. डी. पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर लिखित बयान। ।उसने अन्य बातों के साथ कहा कि वास्तव में यह पति था जो उसके प्रति अपमानजनक और हिंसक था जिससे उसके लिए उसके साथ रहना मुश्किल हो गया था।पति उससे और उसके परिवार से दहेज की मांग करता था, भले ही उसे और उसके

परिवार को अच्छी तरह से प्रदान किया गया था और उसके पास काफी संपत्ति थी।यह दावा किया गया था कि एक पंचायत में, जिसे बुलाया गया था, पति और उसके परिवार ने अपने गलत कामों को स्वीकार किया और यह केवल पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसरण में था, वे जून, 2003 में एक अलग आवास में स्थानांतरित हो गए थे और उसके बाद, 2006 में अपने फ्लैट में।यह आगे दावा किया गया कि पति अपने एक कर्मचारी शीतल के साथ जुड़ा हुआ था और इसी पृष्ठभूमि में बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था और उसने उसे छोड़ दिया था।उन्होंने अपने पति के खिलाफ जिला परिषद का चुनाव लड़ना स्वीकार किया, लेकिन इस बात से इनकार किया कि वह नकारात्मक प्रचार में शामिल थीं या उन्हें परेशान कर रही थीं।तदनुसार उसने पति द्वारा दायर याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया।

(5) पक्षकारों की दलीलों से, एल. डी. द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे। पारिवारिक न्यायालयः-

1. क्या याचिकाकर्ता याचिका में उल्लिखित आधारों पर तलाक की डिक्री का हकदार है?ओपीपी

2. राहत मिलती है।"

(6) दोनों पक्षों ने एल. डी. पारिवारिक न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलों के समर्थन में साक्षय प्रस्तुत किए। पति ने खुद को पीडब्लू-4 के रूप में जाँच किया, इसके अलावा, अपनी बेटी पूजा सहित छह अन्य गवाहों से पीडब्लू-के रूप में जाँच की।

(7) दूसरी ओर, पत्नी ने आर. डब्ल्यू.-7 के रूप में गवाह-प्रपत्र में कदम रखा और अपने मामले के समर्थन में छह अन्य गवाहों से पूछताछ की।दोनों पक्षों ने अपने-अपने मामलों के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए।

(8) पक्षकारों के नेतृत्व में साक्षय और अभिलेख पर अन्य सामग्री का विश्लेषण करने के बाद, एल. डी. पारिवारिक न्यायालय ने पति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और क्रूरता के आधार पर तलाक का फरमान जारी किया।

(9) हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर साक्षय और अन्य सामग्री का पुनर्मूल्यांकन किया है।

(10) तत्काल अपील के लंबित रहने के दौरान, पक्षों को इस न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र को भेजा गया था, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला।इस न्यायालय ने पक्षों के साथ बातचीत भी की।

लंबाई, लेकिन दलों ने अपने-अपने रुख को बनाए रखा जैसा कि एल डी पारिवारिक न्यायालय से पहले लिया गया था। पारिवारिक न्यायालय और एक दूसरे के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराया।इस प्रकार, इस न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र द्वारा पक्षों के बीच सुलह करने के लिए किए गए सभी प्रयास व्यर्थ साबित हुए।

(11) हाथ में मामले के अर्न्तगत पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की थी।पीडब्लू-7/पूजा के बयान को संदर्भित करना सबसे अधिक प्रासंगिक होगा, जो पक्षों की बेटी है और एल. डी. पारिवारिक

न्यायालय के समक्ष अपने बयान के समय लगभग 17 वर्ष की थी। पारिवारिक न्यायालय ।मान लीजिए, पार्टियों के बीच शादी 09.03.1996 पर हुई थी और पार्टियां 2009 तक एक साथ रहती थीं ।इसका मतलब है कि अलग होने के समय यानी 2009 में पीडब्लू-7/पूजा की उम्र लगभग 13 साल थी ।इस प्रकार, वह अपने माता-पिता के बीच मौजूद संबंधों की प्रकृति को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व थी ।इसके अलावा, यह रिकॉर्ड पर स्वीकार किया जाता है कि वर्ष 2009 से, पीडब्लू-7/पूजा और उसका छोटा भाई दोनों प्रतिवादी-पिता के साथ रह रहे हैं ।यह भी रिकॉर्ड की बात है कि दोनों बच्चों को पिता द्वारा बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था, हालांकि पति द्वारा उन्हें बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करने का कारण घर में व्याप्त अस्वस्थ और गैर-अनुकूल वातावरण था, जबकि दूसरी ओर, अपीलकर्ता-पत्नी ने आरोप लगाया कि यह प्रतिवादी-पति की अपने कर्मचारी के साथ कथित संलिप्तता के कारण था, बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पैक कर दिया गया था ।इस पृष्ठभूमि में, पीडब्लू-7/पूजा का बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसने अपीलार्थी-माँ के घर के अंदर और बाहर दोनों के आचरण का स्पष्ट विवरण दिया है ।कल्पना के किसी भी विस्तार से उसके बयान को एक प्रशिक्षित संस्करण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने भाई के साथ लगभग 13 वर्षों तक अपने माता-पिता के साथ रही थी और इसलिए, वे बड़े हो गए थे और घर की पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व थे ।इतना ही नहीं, बेटी ने बयान दिया कि वह अपनी मां के साथ रहने के बजाय छात्रावास में रहना पसंद करती है, जो चंडीगढ़ में उसके स्कूल में जाती है और बदसूरत दृश्य पैदा करती है जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी होती है ।कोई भी बेटी, बहुत कम, 17 साल की लड़की अपनी माँ के खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगाएगी।

(12) निर्विवाद रूप से दोनों पक्ष पिछले 10 से अधिक वर्षों से अलग रह रहे हैं ।प्रत्यर्थी-पति के खिलाफ कई आपराधिक शिकायतें दर्ज करने में अपीलार्थी-पत्नी के कार्य और आचरण, इस तथ्य के साथ कि जिला परिषद चुनाव में उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की उसकी अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच गंभीर वैवाहिक कलह के लक्षण हैं।

(13) हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि न केवल बच्चों के प्रति, बल्कि प्रतिवादी-पति के प्रति भी पत्नी के आचरण से बहुत मानसिक पीड़ा होती, जिससे पति को गहरा दुख होता और उनके पास अपने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता ।यह बहुत स्पष्ट है जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि 2009 से अलग रह रहे पक्षों के बीच किसी भी सुलह की कोई संभावना नहीं है ।पार्टियों के साथ हमारी बातचीत ने भी हमें बिना किसी संदेह के छोड़ दिया है कि पार्टियों के बीच शादी टूट गई है।

(14) यह उल्लेख किया जा सकता है कि अपील के लंबित रहने के दौरान, अदालत में मौजूद अपीलार्थी-पति ने कहा कि हालांकि अपीलार्थी-पत्नी के साथ सुलह करना असंभव

था, लेकिन वह अपीलार्थी-पत्नी को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्थायी गुजारा भत्ता के लिए पचास लाख रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार था।

(15) उपरोक्त की अगली कड़ी के रूप में और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम महसूस करते हैं कि एल. डी. पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री में कोई हस्तक्षेप नहीं है। बुलाया जाता है ।नतीजतन, वर्तमान अपील खारिज हो जाती है और एल. डी. का 08 दिसंबर, 2014 का निर्णय और डिक्री। पारिवारिक न्यायालय को बरकरार रखा गया है ।हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादी-पति अदालत में दिए गए अपने बयान से बंधा रहेगा।

वह एक करोड़ रुपये की राशि जमा करेगा। इस आदेश के पारित होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर, पूर्ण और अंतिम भुगतान के लिए पचास लाख अपीलार्थी-पत्नी के बैंक खाते में स्थायी गुजारा भत्ता के लिए जमा करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रत्यर्थी निर्धारित अवधि के भीतर अपीलार्थी को स्थायी गुजारा भत्ता की उपरोक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वर्तमान आदेश का कोई लाभ नहीं होगा और तत्काल अपील की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि ऊपर बताए गए अनुसार अपील को खारिज करना, स्थायी गुजारा भत्ता के भुगतान पर आधारित है।

ऋतंब्रा ऋषि

अंजना रानी

स्पष्टीकरणः– स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके किसी अन्य उददेष्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता हे। सभी व्यवहारिक और अधिकारीक उददेष्यो के लए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कायान्वयन के उददेष्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।